

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी /
अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला पंचायत, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़,
चम्पावत, चमोली, उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई विभाग

देहरादून : दिनांक: 18 जून, 2009

विषय : वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत
आयोजनागत मदों में धनवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 23.04.2009 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2009-10 में जिला योजना के अन्तर्गत गूल, हीज एवं पाईप लाईन का निर्माण योजनान्तर्गत लेखानुदान के माध्यम से चार माह हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि के सापेक्ष रुपये 25.00 लाख (रुपये पच्चीस लाख मात्र) की धनराशि निम्न विवरणानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्राविधानों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	योजना का नाम	जनपद का नाम	धनराशि (लाख ₹० में)
1	गूल, हीज एवं पाईप लाईन का निर्माण	ऊधमसिंह नगर	8.00
		पिथौरागढ़	3.00
		चम्पावत	8.00
		चमोली	8.00
		योग	25.00

(रुपये पच्चीस लाख मात्र)

- 1- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश सं० 338 / 11-2004/2005 दिनांक 31.03.2005 एवं शासनादेश सं०-1454 / 11-2007-14(05)/2005, दिनांक 06.12. 07 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह धनराशि स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्य पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।
- 3- स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश संख्या 875 / 11-2009-14(05) / 2005 दिनांक 01.06.2009 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रक्योरमेन्ट) नियमावली 2008 में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत किया जायेगा।
- 4- उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययिता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

कमरा.....2

- 5- स्वीकृत धनराशि का खण्डवार/फॉट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा की जायेगी, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय तथा अनुमोदित परिव्यय से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- 6- स्वीकृत धनराशि के सम्पेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।
- 7- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 8- त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का उक्त त्रैमास में पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान सं०-20 के 2702- लघु सिंचाई, 80-सामान्य, 800-अन्य मद, 9103-गूल, हीज एवं पाईप लाईन का निर्माण, 25-लघु निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा० पत्र सं० 97-ए/वित्त-4/2009 दिनांक 10 जून, 2009 से प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(विनोद फोनिया)
सचिव।

संख्या: 995/।।-2009-03(05)/09.तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाय एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लघु सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- 3- अपर सचिव, वित्त, बजट, अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त पौड़ी/हल्द्वानी।
- 7- समस्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तराखण्ड।
- 8- अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- वित्त विभाग (वित्त अनुभाग-4), उत्तराखण्ड शासन।
- 11- नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

(एस०एस० टोलिया)
अनु सचिव